



19 मिनट	8	24	5 + 1	GS1 • 1	GS2 • 21	GS3 • 18
पढ़ने का समय	मुख्य खबरें	संक्षेप में	MCQS + MAINS	पेपर मिश्रण		

01 — आज 2 मिनट में

5 खबरें जो छोड़नी नहीं हैं

1 RBI ने ब्याज दरें 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग की ओर रुख किया

क्यों जरूरी: मौद्रिक नीति और महंगाई प्रबंधन: RBI के रुख और GDP अनुमानों से संबंधित एक प्रमुख GS3 विषय।

GS3 • अर्थव्यवस्था

P

M

2 नवनेथम पिल्लै को UN जांच की निगरानी के लिए 2026 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया

क्यों जरूरी: अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकाय और UN जांच: मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर GS2 और एथिक्स (Ethics) का एक केस स्टडी।

GS2 • अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

3 ECI ने बल्क वोटर नाम हटाने से रोकने के लिए फॉर्म 7 सबमिशन पर कैप लगाई

क्यों जरूरी: निर्वाचन शुचिता और प्रशासनिक सुरक्षा उपाय: मतदाता सूची में राजनीतिक हेरफेर को रोकने से संबंधित एक GS2 विषय।

GS2 • राजव्यवस्था एवं संविधान

P

M

4 सुप्रीम कोर्ट ने 34% पिछड़ा वर्ग आरक्षण रद्द करने का फैसला बरकरार रखा

क्यों जरूरी: आरक्षण की सीमाओं की न्यायिक समीक्षा और अनुभवजन्य डेटा (Empirical Data) की आवश्यकता: GS2 राजनीति और सामाजिक न्याय का एक केस स्टडी।

GS2 • राजव्यवस्था एवं संविधान

P

M

5 धोखाधड़ी के कारण अमेरिका ने माइक्रोसॉफ्ट, इंफोसिस और TCS को लेबर प्रोग्राम से बाहर किया

क्यों जरूरी: श्रम प्रवास और नियामक अनुपालन: द्विपक्षीय श्रम गतिशीलता पर एक GS2 केस स्टडी।

GS2 • अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

M

आज का आँकड़ा

7.1%

वर्ष 2026-27 के लिए संशोधित GDP ग्रोथ फोरकास्ट।

GS3 · अर्थव्यवस्था

P

M

RBI ने ब्याज दरें 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग की ओर रुख किया

चर्चा में क्यों: भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए ब्याज दरों में 25 bps की बढ़ोतरी की और अपने रुख को 'कैलिब्रेटेड टाइटनिंग' (calibrated tightening) में बदल दिया।

याद रखें

- मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee - MPC) — ब्याज दरें और पॉलिसी स्टैंड तय करने के लिए जिम्मेदार निकाय।
- Calibrated Tightening — महंगाई से निपटने के लिए RBI द्वारा अपनाया गया नया पॉलिसी स्टैंड (policy stance)।
- 7.1% — वर्ष 2026-27 के लिए संशोधित GDP ग्रोथ फोरकास्ट।

मेन्स कोण जब महंगाई के प्राथमिक कारक मानसून की कमी और वैश्विक तेल कीमतों में अस्थिरता जैसे आपूर्ति-पक्ष के झटके हों, तब महंगाई को नियंत्रित करने में मौद्रिक नीति के उपकरणों की प्रभावकारिता का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/133039

GS2 · राजव्यवस्था एवं संविधान

P

M

ECI ने बल्क वोटर नाम हटाने से रोकने के लिए फॉर्म 7 सबमिशन पर कैप लगाई

चर्चा में क्यों: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के दौरान मतदाता नामों को बड़ी संख्या में हटाने से रोकने के लिए फॉर्म 7 जमा करने की संख्या पर सीमा तय की है।

याद रखें

- फॉर्म 7: मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विशिष्ट फॉर्म।
- भारत निर्वाचन आयोग (ECI): मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) की निगरानी करने वाली संस्था।
- व्यक्तिगत मतदाताओं के लिए दावों और आपत्तियों (claims and objections) के दौरान 10 और निरंतर अपडेट (continuous updation) के दौरान प्रति माह 5 आवेदनों की सीमा निर्धारित है।

मेन्स कोण मतदाता सूची की अखंडता बनाए रखने के महत्व और व्यवस्थित मतदाता दमन को रोकने में चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/133540

GS2 · अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

नवनेथम पिल्लै को UN जांच की निगरानी के लिए 2026 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया

चर्चा में क्यों: नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने अंतरराष्ट्रीय कानून में उनके कार्य और गाजा नरसंहार (Gaza genocide) की जांच के लिए UN द्वारा गठित जांच की निगरानी करने के लिए दक्षिण अफ्रीकी न्यायाधीश नवनेथम पिल्लै को 2026 नोबेल शांति पुरस्कार (Nobel Peace Prize) से सम्मानित किया है।

याद रखें

- नवनेथम पिल्लै — दक्षिण अफ्रीकी जज और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में वर्तमान जज।
- इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर रवांडा (International Criminal Tribunal for Rwanda) — वह संस्था जहाँ Pillay पहले कार्यरत थे।
- नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी — नोबेल शांति पुरस्कार (Nobel Peace Prize) देने के लिए जिम्मेदार संस्था।

मेन्स कोण आधुनिक संघर्षों में अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने और नरसंहार के आरोपों को संबोधित करने में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकायों और संयुक्त राष्ट्र की जांचों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/133529

GS2 · राजव्यवस्था एवं संविधान

P

M

सुप्रीम कोर्ट ने 34% पिछड़ा वर्ग आरक्षण रद्द करने का फैसला बरकरार रखा

चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार की अपीलको खारिज कर दिया है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग (Backward Classes) के लिए 34% आरक्षण को रद्द कर दिया गया था।

याद रखें

- 50% आरक्षण की सीमा (ceiling) — वह सीमा जिसके पार जाने के लिए राज्य को उल्लंघन को सही ठहराने के लिए एम्पिरिकल डेटा (empirical data) प्रदान करना होगा।
- सुप्रीम कोर्ट — आंध्र प्रदेश सरकार के आरक्षण के प्रयास के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
- जस्टिस दिपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागु — वह बेंच जिसने अपीलखारिज कर दी।

मेन्स कोण पिछड़ा वर्ग के लिए सकारात्मक कार्रवाई को न्यायसंगत ठहराने हेतु अनुभवजन्य आंकड़ों की आवश्यकता और 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन करने की संवैधानिक वैधता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/133537

धोखाधड़ी के कारण अमेरिका ने माइक्रोसॉफ्ट, इंफोसिस और TCS को लेबर प्रोग्राम से बाहर किया

चर्चा में क्यों: अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस और लेबर सेक्रेटरी कीथ सॉडरलिंग ने माइक्रोसॉफ्ट और TCS सहित बड़ी टेक कंपनियों के निलंबन (suspension) की घोषणा की।

याद रखें

- परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन (Permanent Labour Certification) प्रोग्राम: टेक फर्म के लिए विदेशी श्रमिकों की आवश्यकता को प्रमाणित करने के लिए एक US प्रोग्राम।
- जे.डी. वेंस: वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स।
- कीथ सॉडरलिंग: US लेबर सेक्रेटरी।

मेन्स कोण भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी-सेवा गलियारे (tech-services corridor) पर श्रम प्रमाणन धोखाधड़ी (labor certification fraud) के निहितार्थों और भारतीय प्रवासियों की प्रवास आकांक्षाओं पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/133299

जापान ने 10 साल में भारत में 10 ट्रिलियन येन के निवेश की योजना बनाई

चर्चा में क्यों: जापान ने भारत में विनिर्माण (Manufacturing) और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अगले 10 वर्षों में 10 ट्रिलियन येन (लगभग \$100 बिलियन) निवेश करने की योजना की घोषणा की है।

याद रखें

- 10 ट्रिलियन येन (लगभग \$100 बिलियन) — भारत में जापान द्वारा 10 वर्षों में प्रस्तावित निवेश।
- 2000 और 2025 के बीच भारत में जापान का निवेश \$48 बिलियन रहा।
- \$98 बिलियन — 2000 और 2025 के बीच चीन में जापान का निवेश।

मेन्स कोण जापान से द्विपक्षीय निवेश के गहन विस्तार से भारत की विनिर्माण क्षमताओं और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/133366

मुंबई में होगी मांगरोल की कमिशनिंग, इंडियन नेवी का तीसरा स्वदेशी जहाज

चर्चा में क्यों: भारतीय नौसेना समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मुंबई में अपने तीसरे स्वदेशी एंटी-सबमरीन (Anti-Submarine) शैलो वॉटर क्राफ्ट, 'मंगरोल' को कमिशन करने के लिए तैयार है।

याद रखें

- मंगरोल: भारतीय नौसेना के लिए तीसरा स्वदेशी एंटी-सबमरीन (Anti-Submarine) शैलो वॉटर क्राफ्ट।
- कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड (Cochin Shipyard Limited - CSL): यह वह संस्था है जो मंगरोल क्राफ्ट (Mangrol craft) का निर्माण करती है।
- Make in India पहल के तहत Mangrol में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री (indigenous content) मौजूद है।

मेन्स कोण रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' पहल किस प्रकार भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और समुद्री सुरक्षा में योगदान देती है, इसका विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/133409

बांग्लादेश ने दिसंबर 2026 की समय सीमा से पहले नई गंगा जल बंटवारा संधि की मांग की

चर्चा में क्यों: बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी ने उम्मीद जताई है कि वर्तमान 30 साल का समझौता 12 दिसंबर, 2026 को समाप्त होने से पहले भारत के साथ एक नई गंगा जल साझाकरण संधि (Ganga Water Sharing Treaty) की जाएगी।

याद रखें

- गंगा वॉटर शेयरिंग ट्रीटी (Ganga Water Sharing Treaty) — यह कम पानी वाले सीजन (1 जनवरी से 31 मई) के दौरान फरक्का बैराज पर पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है।
- Joint Rivers Commission (JRC) — भारत और बांग्लादेश के बीच जल सहयोग पर चर्चा करने के लिए द्विपक्षीय तंत्र (bilateral mechanism)।
- पद्मा नदी — बांग्लादेश में प्रवेश करने पर गंगा नदी का नाम, जो फरक्का बैराज (Farakka Barrage) से 22 किमी नीचे स्थित है।

मेन्स कोण भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने में सीमा पार जल-साझाकरण समझौतों के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/upsc/note/133268

GS1 · इतिहास · समाज · भूगोल

आंध्र प्रदेश में Census 2027 का दूसरा फेज पूरा करने के निर्देश

GS2 · राजव्यवस्था · शासन · सामाजिक न्याय · अंतर्राष्ट्रीय संबंध

लेबनान संघर्ष: इजरायल के दोबारा तेज हुए हमलों के परिणामस्वरूप 9,000 से अधिक मौतें हुईं और 2026 तक 6 प्रतिशत की आर्थिक गिरावट (economic contraction) का अनुमान है।

माइक्रोसॉफ्ट और टाटा समेत 8 कंपनियों पर यूनाइटेड स्टेट्स ने लगाया बैन

इथियोपियन सेना ने मेकेले में एंट्री की, 2022 प्रिटोरिया सीजफायर खत्म

NEET-UG परीक्षा: पार्लियामेंट्री कमेटी ने निष्पक्षता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (Computer-Based Test) मोड में बदलाव की सिफारिश की है।

जोश टीम: कडलूर जिला कलेक्टर ने 2030 तक 'ट्यूबरकुलोसिस-फ्री इंडिया' (Tuberculosis-Free India) लक्ष्य को गति देने के लिए 'जॉइंट स्क्वाड फॉर हेल्थ' (Joint Squad for Health) लॉन्च किया।

अनुच्छेद 201: केरल सरकार एक प्रस्ताव (resolution) के जरिए राष्ट्रपति से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बिल (Private Universities Bill) पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करेगी।

केरल कल्याणकारी प्रोजेक्ट्स: सरकार ने 100-दिवसीय कार्यक्रम के तहत स्टडी रूम और अंबेडकर गांवों सहित 32 प्रोजेक्ट्स पूरे किए।

तेलंगाना में 24 मीटर से कम ऊंची इमारतों के लिए अब Fire NOC नहीं चाहिए

KPSC भर्ती: कर्नाटक हाई कोर्ट ने फर्जी सर्टिफिकेट्स के बावजूद नियुक्ति आदेश जारी करने के KSAT के फैसले को बरकरार रखा।

मेट्रो स्टेशन बंद: सुप्रीम कोर्ट ने नियोजित विरोध प्रदर्शनों से पहले 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और बैरिकेडिंग के संबंध में दिए गए तर्कों पर सुनवाई की।

मतदाता सूची: सुप्रीम कोर्ट ने 37.05 लाख लंबित अपीलों के मुकाबले पश्चिम बंगाल के लाखों मतदाताओं को शामिल करने को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया।

चीन से ट्रेड रूट्स को बचाने पर तोमोहिको तानिगुची और संजय कुमार वर्मा की चर्चा

GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा

व्हाइट ड्वार्फ्स: मैग्नेटाइज्ड कार्बन-ऑक्सीजन व्हाइट ड्वार्फ्स (White Dwarfs) 1.4 सोलर मास की चंद्रशेखर लिमिट (Chandrasekhar limit) से अधिक हो सकते हैं।

रोड इन्वेस्टमेंट: हैदराबाद में ₹25,000 करोड़ के रोड इन्वेस्टमेंट प्लान पर चर्चा के लिए 85th Indian Road Congress की मेजबानी की जाएगी।

तेलंगाना में सेमीकंडक्टर और लॉजिस्टिक्स के लिए आएंगी 10 नई जनरेशन पॉलिसीज

कर्नाटक को मिला 9 GW विंड पावर क्षमता के लिए बड़ा अवॉर्ड

तेलंगाना-CRUTI प्रोजेक्ट: DEA ने वारंगल में ₹7,143 करोड़ के सीवरेज प्रोजेक्ट के लिए KfW से ₹5,000 करोड़ की फंडिंग को मंजूरी दी।

GCC की ग्रोथ: भारत का GCC इकोसिस्टम FY26 तक बढ़कर 2,117 सेंटर्स तक पहुंच गया, जिसमें 2.36 मिलियन लोग कार्यरत हैं।

मुंबई में पटाखों पर बैन: बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद, मुंबई पुलिस ने 4 दिसंबर, 2026 तक पटाखों और लेजर लाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है।

आइसक्यूब वेधशाला: फ्रांसिस हैलज़ेन को हाई-एनर्जी कॉस्मिक न्यूट्रिनो (high-energy cosmic neutrinos) की खोज के लिए भौतिकी का 2026 नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।

रोड सेफ्टी मिशन: तमिलनाडु सरकार ने राज्य में हुई 18,449 मौतों के बाद ₹500 करोड़ की पहल की घोषणा की है।

डोनाल्ड ट्रंप के PERM सस्पेंशन से भारत बनेगा AI और GCC का ग्लोबल हब

प्रोटीन और मसल मास पर गलत दावे, FSSAI ने कई कंपनियों को नोटिस जारी

- 1 RBI द्वारा अनुमानित 2026-27 के लिए संशोधित GDP ग्रोथ फोरकास्ट क्या है?
- (a) 8.2% (b) 7.5%
(c) 6.7% (d) 7.1%
- 2 वर्तमान में नवनेथम पिल्लै (Navanethem Pillay) किस अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्था (International Judicial Body) में जज के रूप में कार्यरत हैं?
- (a) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) (b) यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय
(c) वर्ल्ड बैंक (d) अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)
- 3 भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची (electoral rolls) पर किए गए उपायों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. दावों और आपत्तियों (claims and objections) के दौरान व्यक्तिगत मतदाताओं के लिए आवेदन की संख्या 15 तक सीमित है।
 2. मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए Form 7 का उपयोग किया जाता है।
 3. निरंतर अपडेटिंग (updatation) के दौरान प्रति माह 5 आवेदनों की कैप (cap) लागू होती है।
- ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
- (a) केवल 1 (b) केवल 3
(c) केवल 1 और 2 (d) केवल 2 और 3
- 4 सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के लिए आरक्षण की वह सीमा (reservation ceiling) क्या बताई है, जिसे उल्लंघन के लिए अनुभवजन्य डेटा (empirical data) के साथ न्यायोचित ठहराया जा सकता है?
- (a) 40% (b) 60%
(c) 50% (d) 33%
- 5 टेक फर्म द्वारा विदेशी श्रमिकों की आवश्यकता को प्रमाणित करने के लिए किस US प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है?
- (a) ग्लोबल टैलेंट इनिशिएटिव (b) परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम
(c) एम्प्लॉयमेंट ऑथोराइजेशन सिस्टम (d) H-1B वीज़ा स्कीम

मेन्स अभ्यास

आज एक उत्तर लिखें

GS3 • अर्थव्यवस्था

जब महंगाई के प्राथमिक कारक मानसून की कमी और वैश्विक तेल कीमतों में अस्थिरता जैसे आपूर्ति-पक्ष के झटके हों, तब महंगाई को नियंत्रित करने में मौद्रिक नीति के उपकरणों की प्रभावकारिता का विश्लेषण कीजिए।

(9) 5 (10) 4 (11) 3 (12) 2 (13) 1 • 2025



टेलीग्राम



वेबसाइट

हर सुबह टेलीग्राम पर पाएँ

रोज़ सुबह 5 बजे पीडीएफ + क्विज़ • हर रविवार साप्ताहिक • हिंदी और अंग्रेज़ी • मुफ्त, बिना साइन-अप।

t.me/satyadheesh • satyadheesh.in/upsc/reports

कोई गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक या फॉर्मेट चाहिए? हमें लिखें, हम हर मेल पढ़ते हैं:

contact@satyadheesh.in

नोट्स सत्याधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।